

અધ્યાત્મ

वर्ष : 09 अंक : 36

प्रयागराज, रविवार 07 मई, 2023

हिन्दी दैनिक

ਪ੍ਰਾਚ—4

मूल्य : 3 रुपया

ओपीएस कर्नाटक में बना चुनावी मुद्दा, कांग्रेस ने किया लागू करने का वादा

बगलुरु। कनाटक में 10 मई का हान वाले विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय पंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करने और पुरानी पंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी और निराशा को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने बाजार से जुड़े एनपीएस को समाप्त करने वाले राज्यों का अध्ययन करके ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जाहिर है कि चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी से बचने के लिए पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंत में यह कदम उठाया है। राज्य के मतदाताओं में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पंशनभोगी हैं। ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ओपीएस के बादे के बाद यह विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बन गया। घोषणापत्र में लिखा है, 2006 से सेवा में शामिल पंशन के पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस के विस्तार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए। घोषणापत्र में पांच गारंटीयों के बाद यह पार्टी के सबसे बड़े वादों में से एक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के.



पश्चिम योजना हो जा । 1 अप्रैल 2006 के बाद सरकारी सेवाओं में नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए है। ये कर्मचारी एनपीएस से खुश नहीं हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के बैंगलुरु शहर के अध्यक्ष मोहन दसारी ने बात करते हुए बताया कि उनकी पार्टी ने पंजाब राज्य में पहले ही ओपीएस लागू कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारे पास ओपीएस को वापस लाने के लिए स्पष्ट नजरिया है और हम एनपीएस के पूरी तरह से खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, हम देश में सभी को बता रहे हैं कि हम ओपीएस को वापस लाना चाहते हैं। जो नई योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है,

उस दश क बड़ निगम का मदद क
लिए लाया जा रहा है — अडाणी,
अंबानी, टाटा और अन्य। उन्होंने कहा
कि एनपीएस में पैसा शेयरों और
स्पूचुअल फंड में लगाया जाता है। ये
बड़ी कंपनियों के शेयर हैं। जनता के
पैसे से वे कॉरपोरेट की दौलत बढ़ाना
चाहते हैं। वहीं पुरानी पेंशन योजना
पूरी तरह से लोगों के लिए थी। मोहन
दसारी ने बताया कि पहले सेवानिवृत्ति
के समय सरकारी कर्मचारियों को बड़ी
रकम मिल रही थी। चूंकि यह बाजार
से जुड़ी योजना है, इसलिए सेवानिवृत्ति
के समय अब उन्हें उतना पैसा नहीं
मिलता है। आम तौर पर सभी मध्य
यवर्गीय सरकारी कर्मचारी घर बनाने,
बच्चों की शादी करने के लिए
सेवानिवृत्ति का इंतजार करते हैं। उन्होंने
कहा कि अब बाजार योजना के साथ
वे किसी चीज का इंतजार कैसे करेंगे?
इसका मतलब यह भी है कि सरकारी
कर्मचारियों को अच्छी पेंशन भी नहीं
मिलने वाली है। मध्यमवर्गीय सरकारी
कर्मचारी पेंशन पर ही जीते हैं। वे उस
राशि को पाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष
करते हैं। मोहन दसारी ने कहा, यह
विशुद्ध रूप से कॉरपोरेट्स की मदद
करने के लिए है। यह भाजपा और
कांग्रेस सरकारें कर रही हैं। हम इसके
पूरी तरह से खिलाफ हैं और ओपीएस
को वापस लाने के लिए ढ़ढ़ हैं।

वाद के बार म पूछ जान पर, माहनदिसारी ने सवाल किया कि कांग्रेस सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस क्यों नहीं लाई, जहां वह शासन कर रही है? वे अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कांग्रेस के पास ओपीएस के लिए कोई विजन है, तो उसे दोनों राज्यों में इसे लागू करना चाहिए था। चूंकि उन्होंने वहां नहीं किया है, इसलिए वे यहां भी नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ भाजपा विधायकों ने एनपीएस को समाप्त करने की मांग को लेकर विधानसभा से सत्र से बहिर्गमन किया था। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे. मधु स्वामी ने कहा था कि ओपीएस के तहत वेतन और पेंशन का भारी वित्तीय बोझ था। वेतन खर्च 90,000 करोड़ रुपये से अधिक और पेंशन खर्च 20,000 से 24,000 करोड़ रुपये था। भाजपा सरकार ने यहां तक कहा कि उसने उन सभी को एनपीएस के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था जो 2006 के बाद भर्ती हुए थे और वे ओपीएस की मांग नहीं कर सकते। हालांकि, चुनावों में मिली हार की संभावना को देखते हुए भगवा पार्टी ने रुख नरम किया है। देखना यह है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को महज चुनाव में भुनाने के लिए उठाए रहे हैं या उन्हें वार्कइ सरकारी कर्मचारियों की चिंता है।

कर्नाटक में तूफान मचाने के लिए प्रियंका ने कोई कसर नहीं छोड़ी



जपसर लिया। जापाताकगल के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हारने के बाद इंदिरा गांधी चिकमंगलूर सीट से चुनी गई। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि उनका परिवार फिर से संकट में है और उन्हें फिर से इसका समर्थन करने और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने की जरूरत है। बात करते हुए वरिष्ठ नेता और केपीसीसी के प्रवक्ता निजाम फौजदार ने कहा कि कर्नाटक एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि आम आदमी और गरीबों को प्रभावित कर रही है। इसने आज के जीवन में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। प्रियंका गांधी के कर्नाटक आने

स काग्रेस पाटा का समावनाओं का बल ही मिला है। कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र में प्रस्तावित नीतियाँ और कार्यक्रम उनकी लोकप्रियता के कारण पक्कि के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। निजाम फौजदार ने कहा कि वह जहां भी गई हैं वहां रैलियों और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है।

प्रवृत्ति उनकी लोकप्रियता और गांधी परिवार और प्रियंका गांधी के प्रति लोगों की स्वीकृति को इंगित करती है और साधित करती है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्राओं ने आगामी विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में 150 सीटों से आगे जाने की हमारी संभावनाओं को बढ़ा दिया है।

ना संगठन का सिफराजीतक लाने के लिए उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष के पास मोदी सरकार से चुनाव जीतने के लिए और दूसरा विकल्प नहीं रहा जो इस तरह का बयान दिया जा रहा है। जमुई के सांसद ने कहा कि जदयू बताए की किस घटना के आधार पर बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महज एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्ष कर्नाटक में विरोध कर रहा है, तो बाकी के भी विरोधी दल बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं।

न्याय में दर्दी, 12 साल की उम्र में छिन गई थी छत, 93 की उम्र में हाईकोर्ट से मिला पक्ष में फैसला

बंबई। हाईकोर्ट ने आठ दशक से चले आ रहे संपत्ति विवाद मामले में आखिरकार 93 वर्षीय महिला को उसका हक देने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के दो प्लैट उसके मालिक को सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें, प्लैट दक्षिण मुंबई में रुबी मेंशन की पहली मंजिल पर स्थित हैं और 500 वर्ग फुट और 600 वर्ग फुट के हैं। मामला देश की आजादी से पहले का है। 13 जुलाई 1944 में लिखे एक पत्र में बॉम्बे नगर पालिका के तत्कालीन डिप्टी सिस्टी इंजीनियर ने परिसर के तत्कालीन मालिक (वर्तमान मालिक एलायस डिसूजा के पिता एचएस डायस) को सूचित किया था कि दो प्लैटों को नगरपालिका उपयोग के लिए रखा गया था। बाद में बंबई के गवर्नर ने 17 जुलाई 1946 को आदेश दिया कि प्रॉपर्टी के मालिक, डिफँस ऑफ इंडिया नियम के अंतर्गत वह



संपत्तियों को रिक्वीजिशन के दायरे के बाहर कर दिया। 27 जुलाई, 1946 के आदेश में बॉम्बे के कलेक्टर ने निर्देश दिया कि इमारत की पहली मंजिल का कब्जा, जर्हा परिसर स्थित हैं उसे मांग से मुक्त किया जाना चाहिए और मालिक को दिया जाना चाहिए। इस आदेश के बावजूद परिसर का कब्जा मालिक को नहीं सौंपा गया। 08 अप्रैल 1952, 24 मार्च 1952 और पत्र में कहा गया कि उक्त परिसर पर साल 1944 से लॉड का कब्जा है। अंततः 8 मई 1987 को, मालिक ने लॉड को नोटिस जारी कर उक्त परिसर को मांग से मुक्त करने का अनुरोध किया। 1987 से 1991 के बीच मालिक द्वारा रिट याचिकाएँ दायर की गईं लेकिन किसी न किसी कारण से उन्हें वापस ले लिया गया। बाद में बॉम्बे भूमि अधिग्रहण (बीएलआर) अधिनियम

जावानयन के नाम से जाना जाता है। इसे मंगेश डी। लाड (डीएस लॉड के कानूनी उत्तराधिकारी) को जारी किया गया और परिसर में उनके कब्जे के संबंध में सुनवाई के लिए बुलाया गया। विस्तृत सुनवाई के बाद आवास नियंत्रक (सीओए) ने लाड को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिसर खाली करने और राज्य सरकार को खाली कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। सीओए ने निष्कर्ष निकाला कि लॉड द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे किरायेदारी स्थापित नहीं करते हैं। सीओए ने कहा कि डी।एस। लॉड को परिसर में विशिष्ट इरादे से शामिल किया गया था क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी थे। कोर्ट ने कहा कि सरकारी सेवक (आवंटी) की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद सरकारी सेवक या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को परिसर में कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीओए के इस आदेश को लॉड

में हो सकती है कटौती

में हो सकती है कटौती



दादवा और कर्ता रैली में जो गुरुदेव के अवसर ह में भाग टीटी नेताओं और उसी जाना था। इहां, बदले शाह का भी मई तक वह सांस्कृतिकों, राज्य करेंगे और इस यात्रा के दारान वह निक्सा सावजानक रैली को संबोधित नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले महीने बीरभूम में किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अधिकारी और पार्टी के लोकसभा सदस्य सुकांत मजूमदार ने भी पुष्टि की है कि केंद्रीय मंत्री की राज्य यात्रा को एक दिन (9 मई) तक सीमित कर दिया गया है। अब, केंद्रीय मंत्रालय की पश्चिम बंगाल यात्रा को कम करने के लिए राज्य नेतृत्व के दो वर्गों द्वारा दो अलग—अलग कारण बताए जा रहे हैं। शाह का व्यस्त कार्यक्रम कहीं और पुनर्निर्धारित यात्रा का आधिकारिक कारण है। हालांकि, राज्य समिति के एक अन्य सदस्य न कहा कि चूक अगले दिन गुरुदेव की जयंती के कारण बंगाली 8 मई से जश्न के मूड में होंगे, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने एक पूर्ण सार्वजनिक राजनीतिक बैठक रद्द कर दी। पिछली बार अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 14 अप्रैल को बीरभूम के सूरीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया था। बैठक के दौरान, उन्होंने दाव किया था कि अगर भाजपा अगले साल के आम चुनावों में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने में सफल रही, तो तश्शमूल कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल (2026 तक) से बहुत पहले गिर जाएगी।

**म आतकवाद्या का पाएम से बहतर समझता हूँ, उन्हान मरा
दादी और पिता को मारा, बेलगावी में राहुल का मोदी पर हमला**

राहुल गांधी ने आतंकवाद के विषय को लेकर उनकी पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए हमले के बाद पलटवार करते हुए शनिवार को कहा कि आतंकवादियों ने उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या की थी तथा ऐसे में वह आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर समझते हैं। उन्होंने यहां चुनावी सभा में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को 'बहाने बनाने के बजाय कर्नाटक के युवाओं को यह बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में '40 प्रतिशत कमीशन के खिलाफ क्या किया। राहुल गांधी ने कहा, 'प्रधानमंत्री आतंकवाद की बात करते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूँ। मेरे परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा है। आतंकवाद क्या होता है, क्या करता है? इस बात को प्रधानमंत्री से बेहतर मैं समझता हूँ। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फिल्म 'द करेल स्टोरी' को लेकर जारी विवाद का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि वह समाज को तहस-नहस करने वाली 'आतंकी

प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, 'पिछले तीन वर्षों में भाजपा ने कर्नाटक में चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शायद देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की भाजपा सरकार है।

ठेकेदारों के संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 40 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है। आज तक प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, "प्रधानमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या किया? उन्होंने कहा, "इस बार हम क्रांतिकारी कार्य करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक, कांग्रेस ने जिन पांच चुनावी गांरटी की बात है, सरकार में आने के पहले दिन ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने लोगों का आवान किया, "भाजपा को 40 नंबर अच्छा लगता है। पिछले तीन साल उन्होंने 40 प्रतिशत की बात रोज आपको सुनाई। चुनाव में आप भी

कश्मीर मठभेड़: रक्षा नंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी ने सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा

जम्मू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयुक्त ने भी राजनाथ के साथ

राजनाथ सिंह का विषयी वीडियो और उन्होंने बताया कि उत्तरी सेना के कांडी वन क्षेत्र में शुक्रवार को सेना के आतंकवाद-विरोधी अभियान के दौरान आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में पांच जवानों के शहीद होने के एक दिन बाद इलाके का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि राजनाथ कुछ देर जम्मू में रुके और फिर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे व जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजौरी में 'एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान, उन्होंने आतंकवादियों से विचार

राजौरी का दौरा किया। अधिकारियों के अनुसार, जम्मू लौटने से पहले रक्षा मंत्री को कांडी वन क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर, खासकर राजौरी और पुंछ में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले, उत्तरी सेना के कमांडर लेफिटेनेंट जनरल छिवेदी ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। इस दौरान, उन्हें कमांडरों द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के ताजा घटनाक्रमों की जानकारी दी गई। जम्मू के राजौरी और पुंछ को एक दशक से अधिक समय पहले आतंकवाद-मुक्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि, पिछले 18 महीनों में इन दोनों ही जिलों में कई आतंकवादी हमले हुए हैं। कांडी वन क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षाबलों

